केंद्र ने प्रदेश को दी 100 करोड़ की प्रोत्साहन राशि

खनन सुधार में नंबर वन पर रहा उत्तराखंड, खनन क्षेत्र में सुधार कार्यों के लिए पिछले माह भी मिले थे सौ करोड़

देहरादून। खनन क्षेत्र में लगातार सुधारों के चलते प्रदेश को एक बार फिर केंद्र सरकार से बड़ी प्रोत्साहन राशि हासिल होगी। खान मंत्रालय ने वर्ष 2025-26 की विशेष सहायता योजना (एसएएससीआई) के तहत उत्तराखंड को माइनर मिनरल्स रिफॉर्म्स में 100 करोड़ की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि प्रदान की है।

इससे पहले भी माह अक्तूबर-2025 में राज्य को एसएमआरआई रैंकिंग में दूसरा स्थान प्राप्त होने पर 100 करोड़ की प्रोत्साहन राशि (200 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि) मिल चुकी है।

खान मंत्रालय ने 18 नवंबर को जारी कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से बताया कि राज्य ने खनन क्षेत्र से जुड़ी अधिकांश सुधारात्मक प्रक्रियाओं को समय पर और प्रभावी ढंग से लागू किया है। खासतौर पर माइनर मिनरल रिफॉर्म्स से संबंधित सात में से छह प्रमुख सुधारों के मानकों को सफलतापूर्वक पूरा किया है। इस मामले में अन्य राज्यों से उत्तराखंड आगे और नंबर-वन पर रहा है। केंद्र सरकार ने अपनी समीक्षा रिपोर्ट माना है कि उत्तराखंड खनन क्षेत्र में लगातार प्रगति के साथ सुधारों को तेजी से लागू कर रहा है। इसी प्रदर्शन को देखते हुए केंद्र ने वित्त मंत्रालय से राज्य को 100 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि का आदेश जारी किया गया है। संबंधित आदेश में नागालैंड, जम्मू-कश्मीर की तुलना में उत्तराखंड का प्रदर्शन सबसे बेहतर दर्ज किया गया है। ब्यूरो

प्रदेश में खनन क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए ई नीलामी प्रणाली, सैटेलाइट

आधारित निगरानी जैसे कई कदम उठाए गए हैं। सरकार पर्यावरण का ध्यान रखते हुए, अवैध खनन पर लगाम कस रही है, जिसके सकारात्मक परिणाम नजर आने लगे हैं। **-पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री**